vinetur

ब्रिटेन कुछ रिहा अपराधियों को पब्स में जाने से रोकेगा

अधिकारियों ने कहा कि लक्षित पाबंदियां कर्फ्यू, इलेक्ट्रॉनिक टैग और GPS निगरानी के जरिए अपराधियों को भीड़भाड़ वाले आयोजनों से दूर रख सकती हैं।

शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026



ब्रिटिश सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह जेल से रिहा किए गए अपराधियों पर लाइसेंस की नई शर्तें लागू करेगी, जिनमें पब्स में जाने, बड़े सार्वजनिक आयोजनों में शामिल होने और ऐसे अन्य स्थानों पर जाने पर रोक शामिल होगी, जिन्हें आगे अपराध की आशंका बढ़ाने वाला माना गया है।

न्याय मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य पुनःअपराध को कम करना और अपराधियों को ऐसे माहौल से दूर रखकर सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत करना है, जो हानिकारक व्यवहार को उकसा सकते हैं। योजना के तहत लाइसेंस पर रिहा अपराधियों पर कर्फ्यू, इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग और GPS तकनीक के जरिए स्थान-निगरानी भी लागू हो सकती है। ब्रिटिश व्यवस्था में, लाइसेंस पर रिहाई का मतलब है कि व्यक्ति सजा पूरी होने से पहले जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन समुदाय में उस पर सख्त निगरानी बनी रहती है।

मंत्रालय के अनुसार, ये पाबंदियां हर मामले के हिसाब से तय की जाएंगी और समय से पहले रिहाई के लिए मंजूर किए गए अपराधियों पर लागू होंगी। प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस के साथ मिलकर और निगरानी तकनीक की मदद से,

अनुपालन की निगरानी करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि कोई अपराधी शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे तुरंत जेल वापस भेजा जा सकता है।

सरकार ने इस पैकेज को ब्रिटेन में अब तक लागू किए गए लाइसेंस प्रतिबंधों का सबसे कड़ा सेट बताया। यह आकलन न्याय मंत्रालय ने किया, जिसने कहा कि उसने यह दृष्टिकोण पुलिस और प्रोबेशन सेवाओं के साथ समन्वय में विकसित किया और पहले के निगरानी कार्यक्रमों से मिली सीख का इस्तेमाल किया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह नीति बार-बार अपराध करने को लेकर जनता की चिंता का जवाब है।

घोषणा में हर मामले के लिए पूरी कार्यकारी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि अधिकारी स्थान-आधारित प्रतिबंधों के व्यापक इस्तेमाल के पक्ष में हैं। इनमें न केवल पब्स और क्लब शामिल हो सकते हैं, बल्कि फुटबॉल मैच और अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजन भी, जहां तनाव, शराब का सेवन या बड़े समूहों में पहचान छिप जाना निगरानी को जटिल बना सकता है। मंत्रालय ने कहा कि लक्ष्य अपराधियों को उन स्थितियों में लौटने से रोकना है जो उनके पिछले व्यवहार से जुड़ी हैं या जिन परिस्थितियों में नए अपराध की संभावना बढ़ जाती है।

यह नीति अपराध और अपराधी प्रबंधन पर सख्त रुख दिखाने की सरकार की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। मंत्रियों पर लगातार दबाव रहा है कि वे जनता को भरोसा दिलाएं कि हिरासत से रिहा किए गए लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, खासकर तब जब समय से पहले रिहाई के फैसले राजनीतिक जांच के दायरे में आते हैं। विस्तृत लाइसेंस शर्तों और कड़े प्रवर्तन पर ध्यान देकर सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि जेल से रिहाई के साथ समुदाय में नियंत्रण भी और सख्त रहेगा।

इस कदम के पेय और आतिथ्य कारोबार पर भी व्यावहारिक असर हो सकते हैं, भले ही सरकार ने इस नीति को व्यावसायिक संदर्भ में प्रस्तुत न किया हो। पब्स, बार, क्लब और शराब परोसने वाले अन्य स्थल, ज्ञात उच्च-जोखिम व्यक्तियों से जुड़े मामलों में, अधिक स्पष्ट सुरक्षा प्रक्रियाएं बनाए रखने और स्थानीय पुलिस के साथ करीबी समन्वय के दबाव में आ सकते हैं। कुछ इलाकों में संचालकों से प्रतिबंधित ग्राहकों या उन आयोजनों के आसपास अधिक सतर्क रहने को कहा जा सकता है, जहां लाइसेंस शर्तें उपस्थिति सीमित करती हैं। दिन-प्रतिदिन के संचालन में यह कितना बदलाव लाएगा, यह संभवत: इस पर निर्भर करेगा कि स्थानीय प्रोबेशन और पुलिस टीमें नियमों को कैसे लागू करती हैं।

पेय क्षेत्र के लिए यह नीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पब्स और क्लबों का नाम स्पष्ट रूप से उन जगहों के रूप में लिया गया है, जहां कुछ अपराधियों को जाने से रोका जा सकता है। गुरुवार को जारी जानकारी के आधार पर यह सभी स्थलों पर कोई सामान्य नई कानूनी बाध्यता नहीं बनाती, लेकिन जहां अपराधी व्यक्तिगत प्रतिबंधों के अधीन हों, वहां स्टाफ प्रशिक्षण, घटना-रिपोर्टिंग और अधिकारियों के साथ सहयोग की जरूरत बढ़ सकती है। उद्योग समूह और स्थल संचालक संभवत: इस बात पर करीबी नजर रखेंगे कि नियम व्यवहार में कैसे लागू होंगे, इस पर और विस्तृत मार्गदर्शन कब मिलता है।

न्याय मंत्रालय ने घोषणा में यह नहीं बताया कि कितने अपराधियों पर नई शर्तें लागू होने की उम्मीद है या यह नीति इंग्लैंड और वेल्स में कितनी जल्दी लागू की जाएगी। उसने यह भी कोई विवरण नहीं दिया कि किन अपराधों या जोखिम श्रेणियों के कारण पब्स या बड़े आयोजनों पर रोक सबसे अधिक लग सकती है। अदालतें, प्रोबेशन टीमें और जेल प्रशासन जब विशिष्ट मामलों में कड़ी शर्तों का इस्तेमाल शुरू करेंगे, तब ये विवरण महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

फिर भी, सरकार का मुख्य संदेश स्पष्ट था : लाइसेंस पर रिहा अपराधियों पर आने-जाने की जगहों पर व्यापक सीमाएं होंगी, उनकी गतिविधियों पर नजदीकी निगरानी रखी जाएगी, और नियम तोड़ने पर त्वरित कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह संयोजन पुन:अपराध के अवसर घटाने और यह भरोसा बढ़ाने के लिए है कि हिरासत से रिहा लोग कड़े नियंत्रण में बने रहें।